बात वोट की नही देशहित से जुड़ी है

सतबीर गोयत की विशेष रिपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिलायंस जियो के विज्ञापन में दिखने के क्या मायने है ..देश का जनमानस यह धीरे-धीरे समझने लगा है। इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया के बनाए तिलिस्म के भरोसे नरेंद्र मोदी और भाजपा की यह एक सोची-समझी रणनीति थी कि इस देश की जनता को जब चाहे मूर्ख बनाया जा सकता है और इसी अति-आत्मविश्वास में नरेंद्र मोदी भारी गलती कर गए और अपने महिमामंडन के नशे में ये यह तक भूल गए कि उनकी प्राथमिकता लगातार घाटे में जा रहे BSNL को संभालना है ...न कि रिलायंस की 4 प्रतिशत सिम बेचना ।

अंबानी और अडानी जैसे फिरकापरस्त उद्योगपतियों के पैसे पर अपनी राजनीति चमका कर खुद को भारत माँ का लाल बताने वाले देश के धुरंधर प्रधानमंत्री एक के बाद एक हर क्षेत्र, हर दिशा में वर्षों से कार्यरत सरकारी ढांचों और उपक्रमों को ध्वस्त कर अपनी भारत माँ को चंद उद्योगपतियों के हाथों बेचने पर आमादा है।

टेलीकॉम सेक्टर के जानकार ये भी संभावना जताते हैं कि जल्द ही बीएसएनएल स्वयं के लिए स्पेक्ट्रम लेने की बजाय इसी रिलायंस के स्पेक्ट्रम से शेयरिंग प्राप्त करेगा । यानी कि अब बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं रिलायंस से उधार लेकर चलेंगीं।

लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर पहला ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें मोदी सरकार ने रिलायंस के प्रति अपनी गहरी स्वामिभक्ति का परिचय दिया हो । आपको बताते चलूं कि ऐसी कई करतूतें मोदी सरकार पिछले दो साल में एक बार नहीं कई बार कर चुकी है चाहे वो डिफेन्स में एफडीआई लागू होने पर सरकार की तरफ से लाइज़िनंग करने के लिए रिलायंस को नियुक्त करना हो या फिर मोदी के प्रधान मंत्री बनने के 4 महीने के भीतर ही रिलायंस के देश भर में बंद पड़े 19 हज़ार से ज़्यादा पेट्रोल पम्प्स का खुल जाना हो ।

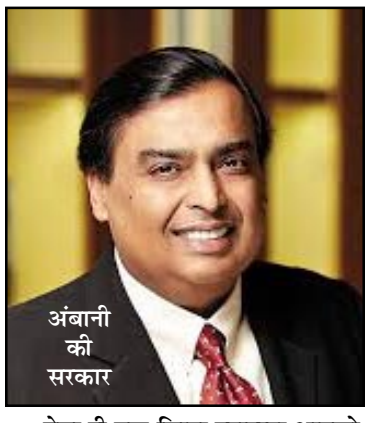

ऐसा ही एक जिन्दा उदाहरण आपको मिलेगा ओएनजीसी के मामले में। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सरकार के एक अति महत्वपूर्ण उपक्रम तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) को दो बड़े झटके देते हुए उसे इस दयनीय हाल में ला दिया है जहाँ से शायद आने वाले दस सालों के अंदर ओएनजीसी का नामोनिशान ही मिट जाएगा।

पहले झटके के तौर पर मोदी ने ओएनजीसी में निजी निवेश को मंजूरी दे दी और इसमें निवेश किया उनके आका मुकेश अंबानी ने। गौर करने वाली बात यह है कि ओएनजीसी भारत सरकार के लिए एक निरंतर मुनाफ़ा देने वाला उपक्रम था, यानी उसकी वित्तीय स्थिति में ऐसी कहीं भी कोई समस्या नहीं जिसके चलते निजी निवेश से धन जुटाने की ज़रूरत पड़े । देखते ही देखते एक पुराने और लगातार लाभ देने वाले सरकार के इस उपक्रम से बिना कुछ किए कराए भारी मुनाफा कमाने लगी रिलायंस ! और बहाना ये बनाया गया कि इससे सरकारी खजाने को एकमुश्त 1600 करोड़ रुपए मिले ।

मोदी यहीं नहीं रुके, इस मंजूरी के बाद उन्होंने ओएनजीसी को और बड़ा तगड़ा झटका दिया और ओएनजीसी के सबसे बड़े सप्लाई हेड्स या फिर साधारण भाषा में यूं कहे कि सबसे बड़े ग्राहक में से एक भारतीय रेलवे को डीज़ल सप्लाई करने का काम ओएनजीसी से छीनकर मोदी ने अपने आका मुकेश अम्बानी की कंपनी "रिलायंस पेट्रोलियम" को दे दिया । अब ओएनजीसी दो तरह से पीटा जा रहा है, पहला जो काम उसके पास है उसमें से कमाए हुए पैसे में भी मुकेश अंबानी का हिस्सा दे और पुराने ग्राहकों को भी एक-एक करके रिलायन्स को सौंपा जा रहा है और ज़ाहिर है इसमें ओएनजीसी को तो कोई हिस्सा मिलना नहीं है ।

अब रही बात कि ये सारी जानकरियाँ सार्वजानिक क्यों नहीं होती। इस समय देश में हिंदी और गैरहिन्दी भाषी लगभग 90 से ज़्यादा चैनल्स है जिन्हें 24 घंटे प्रसारण की अनुमति प्राप्त है। ये 90 से ज़्यादा चैनल्स आज से तीन साल पहले तक 39 अलग-अलग मीडिया ग्रुप्स द्वारा संचालित किए जाते थे। आपको ये जानकर यह आश्चर्य होगा कि चैनल्स की संख्या वही है लेकिन संचालन करने वाले ग्रुप्स 39 से सिर्फ 21 रह गए है।

ऐसा इसलिए क्योंकि इन तीन सालों में नेटवर्क नामक एक मीडिया ग्रुप ने 18 ग्रुप्स को खरीद कर अधिग्रहीत कर लिया। और इस नेटवर्क 18 ग्रुप्स के मालिक का नाम है मुकेश अंबानी।

यानी जो न्यूज़ चैनल्स पर हर शाम आपको गाय, गोबर, गौमूत्र, लवजिहाद, पाकिस्तान, चीन और मंदिर मस्जिद दिखाया जाता है जिसे देखकर आपका खून खौल उठता है वो कोई जोश नहीं बल्कि एक तरह का ड्रग्स है जो आपकी भावनात्मक नसों में घोला जा रहा है ताकि आप के अन्दर अपने ही देश को लूटने वाले चंद गद्दार तथाकथित राष्ट्रवादियों और उद्योगपतियों को देखने और देखकर प्रतिकार करने की क्षमता देश के लोगों में न रह पाए ।

यूँ समझ लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी-II का जन्म इस बार भारत के अंदर ही हुआ है और इसे सुरक्षा देने वाली "खाकी चड्डी" पुलिस तो है ही ।

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोग़ों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में

खाता संख्या : 451102010004150

IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5**
2. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
4. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे**
5. **राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने**
6. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास**
7. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**

गतांक की चीर-फ़ाड़

चैनलों ने तो पत्रकारिता की कंट्रोल लाइन ही उड़ा दी

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

2008 में मुम्बई के आतंकी हमले के दौरान तत्कालीन यूपीए सरकार ने मीडिया के लिये दिशा-निर्देश किए थे कि पत्रकार कोई अपुष्ट जानकारी प्रसारित नहीं करेंगे और सरकार की ओर से उन्हें मुनासिब जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने इन सारे दिशा-निर्देशों को भुला दिया और सरकार की ओर से कोई ब्रीफ़िंग नहीं की गई। सरकार ने कभी साफ़ नहीं किया कि बालाकोट पाक अधिकृत कश्मीर में है या पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सूबे खैबर-पखतून में और हमले में पाकिस्तान को हुए नुकसान का ब्यौरा देने से भी परहेज किया। कई चैनल और समाचार पत्र पत्रकारिता की सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर राजनीतिक दलों की तरह काम करने लगे और युद्धोन्माद फ़ैलाने में जुट गए, जिसका बालाकोट में 300 आतंकी मरे या नहीं....भारतीय मीडिया ने अपनी नाक जरूर कटवा ली--बालाकोट में आतंकियों के मारे जाने की संख्या पर मोदी सरकार अब तक न तो कोई बयान दे सकी न सफ़ाई' में सटीक विश्लेषण किया गया है।

मज़दूर मोर्चा के 10-16 मार्च 2019 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, व साहित्यिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोनों भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा कर रहे हैं और मोदी जी तो यह भी दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने भ्रष्टों को दंडित करने के लिये सब कुछ किया। दरअसल वास्तविकता कुछ और ही है। उन्होंने अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से सम्बन्धित व्यक्तियों के भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी के विरुद्ध अपनी आंखें बंद कर रही हैं।

'आरएसएस के हरियाणा चीफ़ ने ठगे 250 करोड़-पवन जिंदल के घर की महिलाएं फरार-जाल में फसने वालों में हैं कई जाने माने वीआईपी चेहरे भी, बड़ा स्कैंडल-बड़े लोग' में आरएसएस के हरियाणा के प्रांतीय संघ चालक पवन जिंदल और उसके परिवार द्वारा सत्ता के साथ गठजोड़ से फ़र्जीवाड़ा करके हरियाणा के 50 से ज़्यादा लोगों को लगभग 250 करोड़ रुपये का चूना लगने का भंडा-फोड़ किया गया है। पवन जिंदल व उसके भाईयों के परिवार की कुछ महिलाओं जैसे श्रुति जिंदल, कमलेश जिंदल आदि को अदालत द्वारा बाकायदा भगोड़ा अपराधी घोषित होने पर भी पुलिस उन्हें गिरफ़्तार से कतरा रही है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा पुलिस के एक दर्जन अधिकारी व जवान दिन-रात इन घोटालेबाज़ों की सुरक्षा में तैनात हैं, फ़िर भी पुलिस इन पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर रही। जाहिर है अभी पुलिस को ऐसा करने के लिये खट्टर सरकार से हरी झंडी नहीं मिली है।

गौरतलब है कि सत्ता से जुड़े पवन जिंदल के पारिवारिक गिरोह की धोखाधड़ी के चंगुल से लोग़ों को बचाने की बजाए हरियाणा पुलिस इनको बाकायदा सुरक्षा प्रदान कर रही है और फ़रार अपराधी महिलाओं की गिरफ़्तारी नहीं कर रही है। यह मोदी सरकार द्वारा भ्रष्टों को दंडित करने के दावे पर करारा झटका है। विडम्बना है कि 'मज़दूर मोर्चा' के अलावा अन्य किसी समाचार पत्र व चैनल ने इस करोड़ों की लूट व पुलिस द्वारा अपराधियों को संरक्षण प्रदान करने की कार्यवाई का कोई संज्ञान नहीं लिया।

इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) के सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बतौर गेस्ट ऑफ़ ऑनर आमंत्रित करने को भारत सरकार ने अपनी कूटनीतिक उपलब्धि माना, परंतु इस सम्मेलन की कार्यवाई से भारत को कुछ नहीं प्राप्त हुआ, जिसकी 'मुस्लिम राष्ट्रों की महफिल में खुली भारत के ढोल की पोल' में समीक्षा की गई है। सुषमा स्वराज ने अपने भाषण में भारत को आतंकवाद से पीड़ित तो बताया लेकिन ना तो पाकिस्तान का नाम लिया और ना पुलवामा हमले का जिक्र किया। आतंकवाद के विषय में उन्होंने कहा कि यह वैचारिक विकृति है, जो धर्म और संप्रदाय का सहारा लेकर अपने इंसानियत विरोधी नापाक मंसूबों को अंजाम देती है। सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित किया गया, वह भारत के लिये बहुत निराशाजनक रहा। प्रस्ताव में कश्मीरियों को भारतीय आतंकवाद का शिकार बताया और कश्मीरियों को पेलेट फ़ायरिंग से अंधा किए जाने की कड़ी निंदा की गई। इन प्रस्तावों से साफ़ जाहिर है कि भारत इस्लामिक देशों का विश्वास जीतने में असफ़ल रहा।

'चैनलों ने तो पत्रकारिता की कंट्रोल लाइन ही उड़ा दी' में स्वस्थ व निष्पक्ष पत्रकारिता के नियम तथा मोदी सरकार के लगभग पांच वर्ष के कार्यकाल में विशेषकर पुलवामा में सीआरपीएफ़ के काफिले पर आतंकवादियों के हमले के बाद इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा निभाई गई भूमिका का आलोचनात्मक विवेचन किया गया है। पत्रकारिता का प्रमुख नियम है कि अपनी भावनाओं और विचारों से परे होकर काम को पूरा किया जाए तथा सभी प्रकार की अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसी भी कीमत पर यथासम्भव सिद्धांतों से समझौता न करने का प्रयास करें। पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे-जैसे तनाव बढा, मीडिया ने आग में घी डालने का काम किया तथा टीवी चैनलों पर चीखते चिल्लाते, बदला लेने, जनता को उत्तेजित करने और सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ़ कार्यवाई करने का दबाव बनाते दिखे।

आज तक, जी टीवी, सीएनएन, न्यूज 18 नेटवर्क, रिपब्लिकन भारत आदि चैनल सुनियोजित तरीके से न केवल सरकार और संघ परिवार के प्रोपगंडे का हिस्सा बन गए, बल्कि देश और समाज में नफरत को हवा देने में लग गए। दूसरी तरफ़ पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलने वाले और देश में उत्तेजना और नफ़रत के खिलाफ़ खुल कर बोलने और सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले टीवी पत्रकारों व बुद्धिजीवियों के विरुद्ध नफ़रत का अभियान चलाया जा रहा है और उन्हें देशद्रोही व पाकिस्तान समर्थक कहा जाता है, जिसकी 'फ़िर ट्रोल किए रवीश, खास दल के आईटी सेल का नफरती अभियान शुरू, बांटे प्रशांत, जावेद और नसीर के नंबर' में बेबाक चर्चा की गई है। दरअसल, मौजूदा दौर में पत्रकारिता व सहिष्णुता अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं और मीडिया का राजनीतिकरण हो चुका है।

पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय मीडिया वायु सेना द्वारा हवाई हमला करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में एक रैली में कहा कि हम बदला लेने में देरी नहीं करते और देश के भीतर घुसकर मारेंगे, जिसका 'युद्धखोर की भाषा बोल रहे हैं पीएम मोदी' में खुलासा किया गया है। इस तरह की भाषा मध्यकालीन सामंती शासक व तानाशाह द्वारा प्रयोग की जाती थी जिसे सेना का कोई चीफ़ भी बोलने से परहेज करेगा। प्रजातांत्रिक देश के राजनीतिक मुखिया को तो और ज़्यादा धीर गंभीर, कूटनीतिक और रणनीतिकार होना चाहिए। मोदी सरकार की उपलब्धि बताते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बालाकोट हवाई हमले में भारत ने शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया, जबकि भारतीय वायु सेना प्रमुख धनोआ ने बताया कि 80 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। इस प्रकार जेटली ने इस मामले में एक और अनावश्यक विवाद खड़ा कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल द्वारा राफेल से जुड़ी फ़ाइलें चोरी होने का बयान देने पर 'देश सुरक्षित हाथों मे-और फ़ाइलें ?-राफ़ेल से जुड़ी फ़ाइलें चोरी', 56 ईंच छाती के मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में पुलवामा में 44 जवान आतंकवादी हमले का शिकार होने और मीडिया द्वारा सरकार की नीति पर कोई प्रश्न न उठाने पर 'अपने 44 जवान पुलवामा में मरवाए जो सिलसिला रुक नहीं रहा। मोदी सरकार और गोदी मीडिया को इस मोर्चे पर कुछ नहीं सीखना ? तथा 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान, आतंकवाद व हिन्दू-मुस्लिम प्रमुख चुनावी मुद्दे बनाने के लिये निर्देश देने पर 'पाकिस्तान, आतंकवाद, हिन्दू-मुस्लिम पर जोर डालो। लोग रोजगार, गरीबी, भुखमरी, काला धन, नोटबंदी, माल्या, नीरव, सब भूल जायेंगे।' कार्टूनों द्वारा उचित व्यंग्य किया गया है।